bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2080 युगाब्द 5125 कुल पृष्ठ –32 जुलाई द्वितीय अंक – 24

वर्तमान

कमल ज्योति

₹20

भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश
प्रदेश पदाधिकारी बैठक
मुख्य अतिथि :

भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश
लोकसभा प्रवास योजना बैठक
श्री बी.एल. संतोष

वर्तमान

कमल ज्योति

संरक्षक

श्री भूपेन्द्र सिंह

सम्पादक

अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक

राजकुमार

प्रकाशक

प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक

ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग

लखनऊ – 1

फोन :– 0522–2200187

फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org

bjpkamaljyoti

bjpkamaljyoti

@bjpkamaljyoti

सम्पादकीय

जिम्मेदारियां और चुनौतियां

भारत का अमृतकाल ''सबका साथ, सबका विकास'' के साथ अन्त्योदय का संकल्प लेकर मोदी जी के नेतृत्व के नव वर्षो में हुए कार्यो के साथ देश भर मे सम्पर्क महाभियान चला जिसमें उ0प्र0 जैसे बड़े राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। जिसके अनुरूप यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कार्य भी किया। जिसके सुखद परिणाम भी है। जिसकी समिक्षा अनुवर्तन के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बी0एल0 संतोष जी के मार्ग दर्शन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ दो दिवसीय गहन विचार विमर्श हुआ।

प्रदेश इकाई ने डेढ़ माह से अधिक समय तक अनवरत अभियान को प्रभावी रूप से सफल बनाने में टीम वर्क व टीम स्पिरिट के साथ काम किया है। इस बैठक में संतोष जी ने कहा कि इसी तरह सहभागिता, समन्वय, सहयोग को कार्य का आधार बनाकर टीम स्पिरिट के साथ आगे भी काम करना है।

महा जनसम्पर्क अभियान के तहत घर-घर सम्पर्क अभियान,लोकसभा रैलियां,व्यापारी सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, सम्पर्क से समर्थन सहित सभी कार्यक्रमों व अभियानों में उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक में महा जनसम्पर्क अभियान की समीक्षा आगामी कार्यक्रमों व अभियानों पर चर्चा की गई। महा जनसम्पर्क अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की केन्द्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के नौ वर्षों की योजनाएं तथा सरकार के साहसिक निर्णय जन-जन तक पहुंचे हैं, यही 2024 में भाजपा की लक्ष्य प्राप्ति का आधार बनेगी। आगामी दिनों में जिम्मेदारियां और चुनौतियां बढ़ने वाली है। इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक कार्यक्रम व अभियान की पूर्व तैयारी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन के तैयार रोडमैप के साथ हर चुनौती से निपटने का तंत्र तैयार करना है। विगत नौ वर्षों में सर्वाधिक कार्य गरीबों वंचितों के कल्याण हेतु किए गए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विगत छह वर्षो में विकास के कीर्तिमान स्थापित किए।

योगी आदित्यनाथ सबसे पहले व्यवस्था में बदलाव व सुधार किया। निवेश व विकास के अनुकूल माहौल बनाया सकारात्मक परिणाम मिल। पचास विकास योजनाओं में उत्तर प्रदेश नम्बर वन पर है। कई योजनाओं में योगी सरकार की उपलब्धि सत्तर वर्षों पर भारी है।

राष्ट्रीय पटल पर एक नया सक्षम और समर्थ उत्तर प्रदेश उभर कर आया है। पांच वर्ष पहले इसे बीमारू प्रदेश माना जाता था। निवेशकों की उत्तर प्रदेश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रगसर है जिसमें सत्ता संगठन का समन्वय अच्छे परिणाम दे रहा है।

bjpkamaljyoti@gmail.com

हमारा एक ही लक्ष्य, विकास भारत का विकास!

भाजपा–नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज मंगलवार को नई दिल्ली के अशोक होटल में एनडीए के घटक दलों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रख कर सबसे एकजुट हो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस बैठक में एनडीए के 38 घटक दल और उनके वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

हाल में ही छक। के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष– देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास– इस मंत्र को NDA ने निरंतर सशक्त किया है। सभी मनीषी नेताओं ने एनडीए को मजबूती देने का काम किया है। हमारे साथ आज प्रकाश सिंह बादल जी और बाला साहेब के सच्चे अनुयायी मौजूद हैं। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास के मंत्र को NDA ने सशक्त किया है। पुराने साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। नए साथियों का भविष्य के लिए स्वागत करता हूं। NDA के 25 सालों की यात्रा के साथ सुखद सहयोग जुड़ा है।

हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। सरकारें बहुमत से बनती हैं, देश सबके साथ से चलती है।

हमारा देश, आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि–कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में NDA की बहुत बड़ी भूमिका है।

NDA नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। N से New India के लिए, D से Developed Nation (विकसित राष्ट्र) के लिए और । से Aspiration of People and Regions (लोगों और क्षेत्रीय आकांक्षा) के लिए। आज सभी का विश्वास NDA पर है। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित–पीड़ित–शोषित–वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास NDA पर है।

हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। सरकारें बहुमत से बनती हैं, देश सबके साथ से चलती है। आज हम विकासशील भारत के निर्माण में जुड़े हैं।

हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है लेकिन जो भी गठबंधन निगेटिविटी के साथ बने, वे सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने नब्बे के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों को इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाईं, सरकारें बिगाड़ीं। जब देश में स्थिर सरकार होती है, तो देश वो फैसले करता है, जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं।

एनडीए का लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था। इसका गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश कालजयी फैसले करता है।

ये हमने श्रद्धेय अटलजी के दौर में भी देखा और पिछले 9 सालों में बार–बार देख रहे हैं। आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। NDA की विशेषता रही है कि हमने विपक्ष में भी सकारात्मक राजनीति की। कभी नकारात्मक

राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन हमने कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी विदेशी मदद नहीं मांगी।

आज हम देखते हैं केंद्र की योजनाओं को विपक्ष की कई सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। ये योजनाएं लागू होती हैं तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने देती। वो सोचते हैं कि अगर मोदी की योजना का लाभ गरीबों को मिला तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? केंद्र की योजनाओं के लिए मुझे कई बार विपक्षी नेताओं को चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं, लेकिन यह अपनी राजनीति के लिए लोगों के बारे में नहीं सोचते।

जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन, परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है।

तमाम उठा–पटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई और देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आलाकमान! निर्णय लेने में

NDA की विशेषता रही है कि हमने विपक्ष में भी सकारात्मक राजनीति की। कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी विदेशी मदद नहीं मांगी।

अक्षमता! पॉलिसी पैरालिसिस! निर्णय लेने में अक्षमता। भांति–भांति के पावर सेंटर्स। अव्यवस्था और अविश्वास! खींचतान और करप्शन! लाखों करोड़ों के घोटाले! पिछली सरकार में क्रेडिट लेने के लिए सब आगे आते थे, लेकिन गलती होने पर दोष सहयोगियों पर डाल देते थे।

विपक्ष के लिए गठबंधन मजबूरी है लेकिन हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं, बल्कि मज़बूती का माध्यम है। भारत, 'Coalition Compulsions' का नहीं, बल्कि 'Coalition Contributions' का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। NDA में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। NDA, एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए की विचारधारा है – Nation First] Security of Nation First. एनडीए की विचारधारा है– Progress First- एनडीए की विचारधारा है– Empowerment of People First-

NDA में हमने संकल्प लिया था कि हम देश की गरीबों को दूर करेंगे। हमने गरीब को सुरक्षा का अहसास दिया,

एक भारत, एक जुट भारत

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए (National Democratic Alliance) की बैठक हुई। इसमें एनडीए के 39 घटक दलों ने भाग लिया। यह बैठक एनडीए की स्थापना के 25 सफल वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई।

शिव सेना के अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने बैठक में एनडीए का प्रस्ताव रखा। एआईएडीएमके के श्री के. पलानीसामी जी और असम गण परिषद् के श्री अतुल बोरा जी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों ने संकल्प लिया गया कि एनडीए एकजुट होकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लोक सभा चुनाव लड़ेगा और लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।

प्रस्ताव

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में एनडीए सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की परिकल्पना को वास्तविक अर्थों में साकार किया है। एनडीए सरकार में देश प्रगति की नई उचाईयों को छू रहा है। सुशासन व विकास की यात्रा में देश के सभी वर्गों, क्षेत्रों व समुदायों की भागीदारी है। एनडीए अपने स्वरूप में 'एक भारत, एकजुट भारत' का प्रतिनिधित्व करता है। देश को प्रगति–पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एनडीए के सभी दल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी व लोकप्रिय नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं।

एनडीए के गठन को 25 साल हो गए हैं। इन 25 वर्षों में एनडीए ने सुशासन के उच्च मानक स्थापित किए हैं। एनडीए की सरकार जब भी सत्ता में आई है, उसने राष्ट्र प्रथम की भावना और जनकल्याण के उद्देश्य को सर्वोपरि मानकर काम किया है। 1998 से 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या 2014 से अबतक श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, एनडीए सरकार ने सदैव देश की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समर्थन देते हुए राष्ट्र–निर्माण की भावना के साथ काम किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती, सुशासन की स्थापना, आधारभूत संरचना का निर्माण, गरीबों–पिछड़ों के जीवनस्तर में सुधार तथा विषपटल पर भारत की प्रतिष्ठा जैसे विषय एनडीए सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। विशेषकर पिछले नौ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास की दृष्टि से एनडीए सरकार ने जैसा काम किया है, वो अभूतपूर्व है।

एनडीए के साथी दलों ने निजी स्वार्थों को छोड़ जनसेवा को सर्वोपरि मानकर भारतीय राजनीति के लिए एक महान आदर्श प्रस्तुत किया है। एनडीए की सोच, सिद्धांत और स्वरूप में देशहित प्रथम की मूल भावना हमेशा से रही है। राष्ट्र–निर्माण और जनकल्याण के जिस महान विचार के साथ यह यात्रा 1998 में शुरू हुई थी, आज भी उसी रूप में जारी है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी

उन्हें विश्वास दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे NDA सरकार खड़ी है।

NDA सरकार ने वोटबैंक की राजनीति को विकासवाद की राजनीति में बदला है। जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई।

गरीबों को पीढ़ियों दर पीढ़ी गरीब रखने की इस अवधारणा को NDA ने तोड़ दिया। हम जो कर रहे हैं यही सच्चा न्याय है। NDA में गरीबों, रेहड़ी पटरी वालों को मदद मिल रही है। विश्वकर्मा समाज को भरोसा मिला है कि उन्हें भी मदद मिल सकती है। पहले हमारी माता बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का चलन कम था। वे समाज से कटी थीं, आधी आबादी का ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना मुश्किल था। उन्हें लोन मिला, घर मिला तो तस्वीर बदलने लगी।

जब गरीबों को बैंक से लोन की गारंटी सरकार देती है तो उन्हें सहारा मिलता है। जब हम उन्हें मुफ्त इलाज का भरोसा देते हैं तो उससे परिवार ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। पहले ऐसे परिवारों के पास बीमारी में दो विकल्प होते थे। या अपनों को बीमारी से जूझते देखे या घर मकान गिरवी रखे।

आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य NDA को ही मिला है। 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सकें। मैं चाहूंगा कि अकेडमी से जुडे लोग रिसर्च करें कि सरकार की योजना बनाने, काम करने की गति क्या है। इसमें छक। सरकार टॉप पर होगी।

हमारे लिए बहुत आसान था कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम कोई स्मारक बनवा देते, लेकिन हम देश के कोने कोने में एक लाख अमृत सरोवर बना रहे हैं। हमारी स्पीड, उद्देश्य अभूतपूर्व है। हम मेक इन इंडिया पर भी बल दे रहे हैं और देश के पर्यावरण पर भी ध्यान दे रहे हैं।

पहले सत्ता के गलियारे में जो बिचौलिए घूमते थे, हमने उनको बाहर कर दिया है। जन–धन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति से लगभग 30 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में पहुंचे। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाया है। देश में 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी थे, जिनका जन्म ही नहीं हुआ था उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, वो हमारे दलित, आदिवासियों का था। हमने टेक्नॉलॉजी की मदद से लीकेज की हर संभावना को दूर किया है। हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निर्णय ठोस हैं। NDA दल 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय के अटूट विष्वास का संकल्प लेते हैं। एनडीए सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के साथ–साथ सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों की भी सराहना करता है।

गरीब कल्याण का संकल्प

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में व्यक्त 'गरीब कल्याण' के संकल्पों को साकार करते हुए एनडीए सरकार की लाभार्थी कल्याण की अनेक योजनाओं से गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। दुनिया के विष्वसनीय रिपोर्ट्स के अनुसार भी भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है। जन–धन योजना के तहत बैंक खाते से लेकर पीएम उज्ज्वला योजना के तहत धुंआ मुक्त रसोई तक; स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय से लेकर जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पानी के नल तक; पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे किसानों को आर्थिक संबल देने से लेकर पीएम आवास योजना के माध्यम से भारत के करोड़ों परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास देने तक; छोटे व मध्यम उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर रोजगार व स्व–रोजगार के अवसर सृजित करने जैसे अनेक सराहनीय कार्य गत 9 वर्षों की एनडीए सरकार में हुए हैं। इनके माध्यम से गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। गरीब कल्याण के संकल्प को साकार करने के लिए एनडीए के सभी घटक दल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का मुक्त कंठ से अभिनंदन करते हैं।

सर्वस्पर्शी–समावेशी सरकार

पिछले 9 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाजिक न्याय की मूल भावना के अनुरूप एनडीए की सर्वस्पर्शी–समावेशी सरकार चल रही है। एनडीए की मोदी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए सदैव समर्पित है। वंचित समाज के हितों के लिए आवाज उठाने वाले महान राष्ट्रनायक बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े स्थलों को पञ्चतीर्थ के रूप में स्थापित करने का कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन स्थलों से समाज को समता और समरसता की प्रेरणा मिलती है।

अनुसूचित जाति–जनजाति समाज के हित में पिछले 9 वर्षों में जितने कदम उठाए गए हैं, उतने पहले कभी नहीं उठाए गए। अनुसूचित जाति–जनजाति समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए साल–दर–साल बजट में बढ़ोत्तरी हुई है। मोदी सरकार की लाभार्थी योजनाओं में भी दलित व आदिवासी समाज को प्राथमिकता दी गयी है। दलित समाज के आर्थिक सशक्तीकरण एवं स्व–रोजगार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडअप योजना, मुद्रा योजना के तहत आसान ऋण में प्राथमिकता को मोदी सरकार सुनिश्चित कर रही है। इन योजनाओं का परिणाम है कि एससी–एसटी समाज के लोग शिक्षा, उद्योग, रोजगार, सेवा तथा सामाजिक क्षेत्र में उभरकर आ रहे हैं।

2017 के राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने दलित समाज से आने वाले श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। 2022 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो एनडीए ने अनुसूचित समाज से आने वाली महिला श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया और वे राष्ट्रपति बनीं। यह दिखाता है कि श्री नरेंद्र

सरकार ने बीते 9 वर्षों में भ्रष्टाचार के हर रास्ते को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।

2014 में देश की अर्थव्यवस्था टॉप 10 से बाहर थी, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एनडीए की तीसरी सरकार में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। हमारे पास देश के विकास के अगले 25 साल का विजन है।

पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होती। हमने राजनैतिक सौहार्द्र और शालीनता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। आखिरकार, हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा हैं लेकिन दुर्भाग्य से, आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है – हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। इसके बावजूद हमने राजनीति को कभी भी देश से ऊपर नहीं रखा।

लोकतंत्र की मूल भावना NDA की कार्यशैली में आपको हर जगह दिखेगी। हमने प्रणव दा को भारत रत्न दिया, वे जीवन भर कांग्रेस में रहे, लेकिन उन्हें सम्मान देने में हमने संकोच नहीं किया। ये NDA सरकार ही है जिसने मुलायम सिंह यादव जी, शरद पवार जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, तरुण गोगोई जी, एससी जमीर जी और मुज़फ्फ़र बेग जी जैसे नेताओं को पद्म सम्मान दिये। हमने कभी भी राजनीतिक दल के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इस समय भारत जी–20 को होस्ट कर रहा है, इससे जुड़े प्रोग्राम देश में हो रहे हैं। इनका वेन्यू तय करते समय हमने नहीं सोचा कि कहां किसकी सरकार है। कोरोना में हमने हर पार्टी के हर राज्य के सीएम से बात की, उन्हें हर संभव मदद दी।

हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, विपक्ष देश के लोगों को तोड़ता है। विपक्ष के लोग जिस गलती को बार–बार दोहरा रहे हैं, वो है– देश के सामान्य मानवी की समझदारी को Underestimate करना लेकिन, देश की जनता सब कुछ खुली आँखों से देख भी रही है, और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियां क्यों इकट्ठा हो रही हैं। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा Glue है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है।

अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए विपक्ष पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लेकिन, बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डाल कर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर TMC हमले कर रही है लेकिन, इनके नेता TMC के खिलाफ, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस के नेता और पीडीपी नेता एक दूसरे को कैसी–कैसी गालियां देते थे! आरजेडी और जेडीयू के लोग

मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए अनुसूचित जाति–जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है।

सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के सशक्तीकरण के लिए मोदी सरकार ने दशकों से लंबित पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को पूरा किया है। मोदी सरकार के नीतिगत निर्णय से मेडिकल क्षेत्र के दाखिले में पिछड़ा वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए अवसर बढ़े हैं। शिक्षा और रोजगार में ओबीसी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार के प्रयास अभिनंदन करने योग्य हैं।

'नारी शक्ति' के सशक्तीकरण के उद्देश्य से एनडीए सरकार ने महिला–केंद्रित पहलों को सफलतापूर्वक शुरू किया है। आवासीय योजनाओं के तहत घरों को महिलाओं के नाम पर पंजीकृत करने, महिलाओं के लिए संपत्ति कार्ड वितरण, महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने, महिला उद्यमियों को आसान ऋण उपलब्ध कराने सहित अनेक कदमों से देश की नारी शक्ति के लिए राजनीति, रोजगार–स्वरोजगार, सेवा, रक्षा सहित हर क्षेत्र में अवसरों के द्वार खुले हैं। इसका परिणाम है कि देश की नारी शक्ति की उपस्थिति हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है।

सामाजिक न्याय की मूल परिकल्पना को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने नीतियों और निर्णयों से पूरा किया है। आज देश की राजनीति, सरकार तथा अन्य क्षेत्रों में समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो रही है, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता अभिनंदनीय है। एनडीए इसकी प्रशंसा करता है।

विश्व पटल पर मजबूती से उभरती अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के साथ वैष्विक अर्थतंत्र के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। पिछले 9 वर्षों की एनडीए सरकार में देश ने अबतक का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के कीर्तिमान को भी हासिल किया है। तेजी से मजबूत होती भारत की अर्थव्यवस्था में देश के राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भी सक्रिय भागीदार बनकर उभरे हैं। इसका परिणाम है कि अमृतकाल का भारत रक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता को कम करके निर्यात करने वाला देश बनकर उभर रहा है।

देश के बुनियादी ढाँचे को अभूतपूर्व आयाम देने वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना को आकार देने के लिए एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करता है। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे में विष्व पटल पर अग्रणी भूमिका के रूप में उभर रहा है। भारत में आर्थिक लेन–देन के लिए तैयार यूपीआई मॉडल को लेकर भारत के नेतृत्व को सभी ने देखा और सराहा है।

सक्षम, सबल, सामर्थ्यवान और सुरक्षित भारत

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में भारत रक्षा–सुरक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। अमृतकाल का नया भारत स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्माता बनकर उभरा है। रक्षा उपकरणों का निर्यात करने वाले देश के रूप में भारत उभरा है। सीमा सुरक्षा के मामले में भारत ने पिछले 9 वर्षों में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। सैन्य संसाधन में भारत शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति पर चलते

कैसे–कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे! देश की जनता ने ये सब करीब से देखा है, और देख रही है। जनता जानती है ये मिशन नहीं मजबूरियां है। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता नहीं। ये कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवनभर जिसका अपमान किया उनका अचानक सम्मान करने लगें। उनके कार्यकर्ता भी भ्रमित हैं कि क्या करें।

जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं।

2024 का लोक सभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर छक। को ही अवसर देना है।

देश के लोग तो मन बना चुके हैं लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है, तो उसका बहुत बड़ा असर उसका वैश्विक संबंधों पर होता है। हरेक को लगता है कि अरे भाई! अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी सरकार के साथ रहने दो, चुनाव हो जाए तो नई सरकार आएगी, तब सोचेंगे। स्वभाविक है, कोई दूसरा देश उस सरकार के साथ, जब चुनाव निकट हो तो संबंध बनाने से पहले, सम्मान करने से पहले सौ बार सोचता है।

विदेश की सरकार चुनाव के समय चुनाव होने का इंतजार करता है। जो सरकार जाने वाली होती है, उस पर कोई देश अपना टाईम और एनर्जी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन, अनेकों महत्वपूर्ण देश चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं और उनको मान–सम्मान दे रहे हैं। इतने ही देश भारत के साथ बड़े–बड़े और दूरगामी समझौते कर रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वे भी जान रहे हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। भारत के लोगों का भरोसा किस पर है, दुनिया के लोग जान रहे हैं।

हमारा एक ही लक्ष्य है – विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि–कोटि लोगों की आशा–आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा लेंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ये हमारी गारंटी है।

मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण, देश को ही समर्पित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है लेकिन बदनीयती से मैं दूर रहूंगा, बदनीयती से कोई काम नहीं करूंगा।

हुए भारत शांति और प्रगति के संदेश का वाहक बना है।

कोविड की कठिन चुनौती के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अपने असीम सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है। कोविड महामारी से लड़ाई में भारत के नेतृत्व की दूरदर्शिता को दुनिया भर में सराहना मिली है।

लोकप्रिय नेतृत्व–अटूट विष्वास

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैष्विक मंचों पर भारत की साख मजबूत हुई है। विष्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देशवासियों का अटूट विष्वास हासिल है। अपने यशस्वी नेतृत्व पर 140 करोड़ देशवासियों के विष्वास के कारण ही भारत की साख दुनिया में बढ़ी है। पूरे देश साहित हम सभी के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 14 देशों द्वारा शीर्ष राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। इसमें फ्रांस और खाड़ी क्षेत्र के कई देश शामिल हैं। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के प्रति दुनिया के सम्मान पूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है। यह दुनिया के पटल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व की पहचान है।

भारत के प्रति दुनिया के नजरिये में बदलाव का ही परिणाम है कि विष्व के जटिलतम विषयों पर दुनिया के देश भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे हैं। यह सुखद संयोग है कि इसी कालखंड में भारत जी–20 की अध्यक्षता कर रहा है।

आज का भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा–शब्द 'यही समय है, सही समय है' की भावना के साथ 'चरैवेति–चरैवेति' का मंत्र लेकर विजन–2047 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जनभागीदारी व जनविष्वास के साथ दौड़ चला भारत है।

विजय के विष्वास का संकल्प

2014 के लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनता का जो आशीर्वाद मिला, वह पांच साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में और बढ़ा। विपक्षी दलों के झूठ, अफवाह और बेबुनियाद बयानों को सिरे से नकार कर देश की जनता एनडीए नेतृत्व पर विष्वास जता रही है। विपक्ष अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। आज का विपक्ष भ्रम और भटकाव से घिरा हुआ है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति अडिग विष्वास व्यक्त करते हुए पूरी एकजुटता के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों में 2019 में मिली जीत से भी बड़े जनादेश के साथ विजय के संकल्प का उद्घोष व्यक्त करते हैं। हम पूरी एकजुटता और आत्मविष्वास के साथ संकल्प व्यक्त करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले से भी बड़ा जनादेश और अपार जनआशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलने जा रहा है।

अपनी कर्मशीलता, कर्मठता, अथक परिश्रम तथा देशसेवा के प्रति निस्वार्थ समर्पण से भारत को प्रगति–पथ पर आगे ले जाने तथा अपने नेतृत्व से अनेक अवसरों पर देशवासियों को गौरव की सुखद अनुभति कराने के लिए एनडीए के सभी साथी दल जन–मन के बीच सर्व–प्रिय तथा सर्व–स्वीकार्य जननेता श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। एनडीए घटक सर्वसम्मति से यह संकल्प लेते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की इस विकास–यात्रा के सहभागी के रूप में– हम एक हैं, एकजुट हैं, एकमत हैं।

नफरत, घौटाले, तुष्टिकरण मन काले हैं...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। लगभग 710 करोड़ रुपये की निर्माण लागत के साथ, नया टर्मिनल भवन सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही आज का कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, लेकिन पूरा देश उत्सुकता से केन्द्र शासित प्रदेश की ओर देख रहा है क्योंकि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्री प्रबंधन क्षमता बढ़ाने की मांग पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित रहने की भी इच्छा व्यक्त की क्योंकि वह हर्षित वातावरण और नागरिकों के चेहरों की प्रसन्नता अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "जो लोग अंडमान की यात्रा करना चाहते थे, उन्होंने बड़ी क्षमता वाले हवाई अड्डे की भी मांग की है।"

प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया

पोर्ट ब्लेयर में हवाई अड्डे की सुविधाओं के विस्तार की बढ़ती इच्छा पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक मौजूदा टर्मिनल में 4000 पर्यटकों को संभालने की क्षमता थी, और नए टर्मिनल में यह संख्या 11,000 हो गई है और अब हवाई अड्डे पर किसी भी समय 10 विमान पार्क किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, अधिक उड़ानें और पर्यटक क्षेत्र में अधिक नौकरियां लाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर के नए टर्मिनल भवन से यात्रा में, कारोबार करने में आसानी होगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत में विकास का दायरा लंबे समय तक बड़े शहरों तक ही सीमित रहा है", उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश के जनजातीये और द्वीप क्षेत्र लंबे समय तक विकास से वंचित थे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में वर्तमान सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ न केवल पिछली सरकारों की गलतियों को सुधारा है, बल्कि एक नई व्यवस्था भी बनाई है। "भारत में समावेशन के विकास का एक नया मॉडल सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा, मॉडल 'सबका साथ, सबका विकास' है। उन्होंने बताया कि विकास का यह मॉडल बहुत व्यापक है और इसमें हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग और जीवन के हर पहलू जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी का विकास शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में अंडमान में विकास की नई कहानी लिखी गई है. पिछली सरकार के 9 वर्षों में अंडमान–निकोबार को 23,000 करोड़ रुपये का बजट मिला था, जबकि वर्तमान सरकार के पिछले नौ वर्षों में अंडमान–निकोबार को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसी तरह, पिछली सरकार के 9 वर्षों में 28,000 परिवारों के घरों में नलों से पानी पहुंचाया गया था, जबकि पिछले 9 वर्षों में यह संख्या 50,000 है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आज अंडमान–निकोबार में हर किसी के पास बैंक खाता है और वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा है। पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज के लिए भी वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, जबकि पहले केन्द्र शासित प्रदेश में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। उन्होंने कहा, पहले इंटरनेट पूरी तरह से उपग्रहों पर निर्भर था, अब वर्तमान सरकार ने समुद्र के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की पहल की है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुविधाओं के विस्तार से यहां पर्यटन को गति मिल रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य अवसंरचना, हवाई अड्डे की सुविधाएं और सड़कें पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देती हैं। श्री मोदी ने कहा, इसीलिए, 2014 की तुलना में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है। साहसिक पर्यटन भी फल–फूल रहा है और आने वाले वर्षों में यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी।

प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, "अंडमान विकास और विरासत के महामंत्र का एक जीवंत और आश्चर्यजनक उदाहरण बन रहा है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही लाल किले से पहले अंडमान में तिरंगा फहराया गया था, लेकिन द्वीप पर गुलामी के निशान पाए जा सकते हैं। उन्होंने ठीक उसी स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अवसर मिलने के लिए आभार व्यक्त किया, जहां कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह वर्तमान सरकार ही थी जिसने रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया। उन्होंने 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आजादी के पिछले 75 वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुआ होता क्योंकि भारतीयों की क्षमताओं के बारे में कोई संदेह नहीं है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति ने हमेशा आम नागरिकों की ताकत के साथ अन्याय किया है। प्रधानमंत्री ने कुछ दलों की अवसरवादी राजनीति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति की आलोचना की। उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता की भी आलोचना की, जो कुछ मामलों में जमानत पर हैं और यहां तक कि दोषी भी सिद्ध हो चुके हैं। उन्होंने संविधान को बंधक बनाने की मानसिकता पर प्रहार किया। उन्होंने इंगित किया कि ऐसी ताकतें आम नागरिकों के विकास के बजाय स्वार्थी पारिवारिक लाभ पर केंद्रित हैं। श्री मोदी ने रक्षा और स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत के युवाओं की ताकत को रेखांकित किया

और इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि युवाओं की इस ताकत के साथ न्याय नहीं किया गया।

आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत, कहीं से कहीं पहुंच सकता था और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है–

''गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है'' चौबीस के लिए छब्बीस होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। ''गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, और माल कुछ है'' यानि गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रॉडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं। और दूसरा, ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं।

एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है– एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए, ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं, तो पहला विचार देश के सामने क्याब आता है– पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोलता है– लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो 'कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन' हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है। इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रॉडक्ट है– 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी।

अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए खुद को समर्पित करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वीपों और छोटे तटीय देशों के ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने आज दुनिया में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भले ही प्रगति का मार्ग चुनौतियों से भरा हो, लेकिन विकास हर प्रकार के समाधानों के साथ आता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किए जा रहे विकास कार्य पूरे क्षेत्र को और मजबूती प्रदान करेंगे।

सरकार कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती रही है। लगभग 710 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन, इस द्वीपीय संघ शासित प्रदेश की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लगभग 40,800 वर्गमीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ, नया टर्मिनल भवन सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपये की लागत से दो बोइंग–767–400 और दो एयरबस–321 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त एक एप्रन का भी निर्माण किया गया है, जिससे हवाई अड्डा अब एक ही समय में दस विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त हो गया है।

प्रकृति से प्रेरित, हवाई अड्डे के टर्मिनल का वास्तुशिल्पीय डिजाइन समुद्र और द्वीपों को चित्रित करती शंख की संरचना जैसा दिखता है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत प्रणाली, इमारत के अंदर कृत्रिम प्रकाश के उपयोग में कमी लाने के लिए दिन के समय प्रचुर मात्रा में सूरज की रोशनी का अधिकतम प्रवेश प्रदान करने के लिए रोशनदान, एलईडी प्रकाश व्यवस्था और लो हीट गेन ग्लेज़िंग जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं।

द्वीप समूह के पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए एक भूमिगत जल टैंक में वर्षा जल संग्रहण, 100 प्रतिशत शोधित अपशिष्ट जल को भू–निर्माण के लिए पुनः उपयोग करने वाला एक ऑन–साइट सीवेज शोधन संयंत्र और 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र टर्मिनल भवन की कुछ अन्य विशेषताएं हैं।

अंडमान और निकोबार के प्राचीन द्वीपों के प्रवेश द्वार के रूप में, पोर्ट ब्लेयर पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थल है। विशाल नया एकीकृत टर्मिनल भवन हवाई यातायात को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

कार्यकर्ता की आगामी दिनों में, जिम्मेदारियां, चुनौतियां बढ़ने वाली हैं: संतोष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष जी दो दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर लखनऊ। राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष जी ने प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह जी की उपस्थिति में मुख्यालय पर आयोजित प्रदेश पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक में महा–जनसम्पर्क अभियान की समीक्षा तथा आगामी कार्यक्रमों व अभियानों पर चर्चा हुई।

श्री बीएल संतोष जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता देश में कर्मठता, अनुशासन और अथक परिश्रम से सफलता का पर्याय बने है। महा–जनसम्पर्क अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की केन्द्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्षों की योजनाएं तथा सरकार के साहसिक निर्णय जन–जन तक पहुंचे हैं, यही 2024 में भाजपा की लक्ष्य प्राप्ति का आधार बनेगी। पार्टी की प्रदेश इकाई ने डेढ़ माह से अधिक समय तक अनवरत अभियान को प्रभावी रूप से सफल बनाने में टीम वर्क व टीम स्पिरिट के साथ काम किया है। इसी तरह सहभागिता, समन्वय, सहयोग को कार्य का आधार बनाकर टीम स्पिरिट के साथ आगे भी काम करना है। महा–जनसम्पर्क अभियान की सफलता के लिए पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ ही प्रदेश के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि महा–जनसम्पर्क अभियान के तहत घर–घर सम्पर्क अभियान, लोकसभा रैलियां, व्यापारी सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, सम्पर्क से समर्थन सहित सभी कार्यक्रमों व अभियानों में उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। आगामी दिनों में जिम्मेदारियां और चुनौतियां बढने वाली है। इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक कार्यक्रम व अभियान की पूर्व तैयारी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन के तैयार रोडमैप के साथ हर चुनौती से निपटने का तंत्र तैयार करना है। इसके साथ ही लोकसभा प्रवास योजना के तहत विगत चुनाव में प्रतिकूल परिणाम वाली 14 लोकसभा सीटों में चलाये गये कार्यक्रम, अभियान, प्रवास सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा भी की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया की प्रदेश तथा क्षेत्रीय टीम के साथ भी बैठक में मार्गदर्शन दिया।

प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने संगठनात्मक अभियानों, कार्यक्रमों तथा विगत निकाय चुनाव तथा सहकारिता चुनावों की चर्चा करते हुए कहा कि महा–जनसम्पर्क अभियान के माध्यम से भाजपा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व के सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के 9 वर्षों के उपलब्धियां लेकर प्रदेश की बड़ी आबादी तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष जी का दो दिवसीय प्रवास पार्टी के कार्यक्रमों तथा अभियानों को गति देने के लिए प्रेरणादायी साबित होगा। भाजपा उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी।

प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने मीडिया के साथ अनौपचारिक चर्चा में बताया कि बैठक में तय हुआ कि पार्टी के निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों की कार्यशाला हरियाणा में होगी। इसके साथ ही पार्टी के निर्वाचित सभी जिला पंचायत सदस्यों की कार्यशाला आगामी माह में क्षेत्रवार आयोजित की जाएगी। क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों, नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद तथा नगर पंचायतों के अध्यक्ष व पार्षदों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए चर्चा की गई।

यूपी की तस्वीर बदली...

लखनऊ में 3775 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए नितिन गड़करी ने कानपुर–भोपाल इकोनोमिक कॉरिडोर, गोरखपुर–सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर–शामली ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, वाराणसी से कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गाजीपुर से बलिया माझीघाट लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण की घोषणा की। गड़करी ने लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर नए फ्लाइओवर के निर्माण के साथ गोसाईगंज में बेनी हरौनी क्रासिंग, केसरीखेड़ क्रासिंग, दिलकुशा क्रासिंग, गोमतीनगर विस्तार स्थित भरवाना क्रासिंग, सीतापुर में सीतापुर आरओबी, बिसवा–सीतापुर रेलवे स्टेशन आरओबी और लखनऊ – सीतापुर रोड पर सिधौली में आरओबी के निर्माण की घोषणा की।

महर्षि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गड़करी ने 3300 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ – सीतापुर खंड में मडियांव आईआईएम क्रासिंग पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और अलीगढ़–कानपुर खंड के नवीगंज से मित्रसेनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का लोकार्पण किया। लखनऊ में 435 करोड़ रुपये की लागत से 164 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

कानपुर से लखनऊ के बीच पांच हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 65 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाइवे का 25 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। 2025 से पहले यह हाइवे बन जाएगा। उसके बाद लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी आधा घंटे में तय होगी।

भोपाल–कानपुर इकोनोमिक कारिडोर भी बनाया जाएगा। 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से 480 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से भोपाल–कानपुर के बीच की दूरी सात घंटे में तय होगी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से शामली के बीच 35 हजार करोड़ रुपये की लागत से 840 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं। यह गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ से शामली तक बनेगा। इसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, यह एक्सप्रेसवे यूपी में बड़ी लाइफ लाइन बनेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर गोरखपुर से सिलीगुडी 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से 6 लेन ग्रीनफिल्ड हाइवे बनाया जाएगा। इसकी डीपीआर जल्द तैयार होगी। वाराणसी से कोलकाता तक 25 हजार करोड़ की लागत से नया ग्रीनफील्ड हाइवे बना रहे हैं। वाराणसी से बिहार झारखंड होते हुए कोलकाता की दूरी सात घंटे में तय होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून हाइवे का का उद्घाटन दिसंबर से पहले हो जाएगा।

2024 के अंत तक पांच लाख करोड़ के काम पूरे होंगे

नितिन गड़करी ने कहा कि यूपी में 2024 के अंत तक पांच

लाख करोड़ की परियोजनाओं के काम समाप्त करेंगे और कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से 2022 तक छह हजार किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा किया है। करीब सवा लाख करोड़ की लागत से तीन हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण चल रहा है। 80 हजार करोड़ रुपये लागत से बनने वाली 3500 किलोमीटर सड़कों की डीपीआर बन रही है। भविष्य के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये लागत की 120 परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं।

यूपी की तस्वीर बदली

नितिन गड़करी ने कहा कि एक समय था जब यूपी की पहचान गरीब प्रदेश के रूप में थी। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर बदली है। योगी ने जिस प्रकार कानून व्यवस्था में सुधार किया है उससे पूरे देश की जनता उन्हें धन्यवाद दे रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में दस लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है। निवेश तब ही आता है जब ऊर्जा, जल, परिवहन और कम्यूनिकेशन की सुविधा हो। निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेता तो गरीबी दूर होगी।

एथेनॉल से अब हवाई हवाज भी चलेंगे

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब यूपी के एथेनॉल से केवल गाड़ी ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में दुनिया में हवाई जहाज एविएशन फ्यूल बनकर चलेगा। इंडियन ऑयल की ओर से इसका प्लांट स्थापित किया जा रहा है। जिससे किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। एथेनॉल, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन हमारा भविष्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूपी को हाइड्रोजन निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। देश ऊर्जा को आयात नहीं, निर्यात करने वाला देश बनेगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने लखनऊ के लोकार्पण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी एवं सीएम योगी आदित्य नाथ के गोरखपुर में 75 हजार करोड़ से तीन ग्रीन एक्सप्रेस का तोहफा दिया है। इनमें दो ग्रीन एक्सप्रेस वे गोरखपुर और एक वाराणसी में बनेगा। आईआईएम रोड स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्ममेशन टेक्नोलॉजी परिसर में मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर में गोरखपुर–सिलीगुढी एवं गोरखपुर–शामली और वाराणसी– कोलकाता ग्रीन एक्सप्रेस का निर्माण करने का डीपीआर तैयार हो रहा है। यह तीनों परियोजनाएं 25–25 हजार करोड़ रूपये की हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेस वे बनने से वाराणसी से कोलकाता का सफर सात घंटे में पूरा हो जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली–देहरादून 162 किमी का एक्सप्रेस वे का कार्य सितंबर तक पूरा हो जाएगा, जिस पर इसी साल दिसंबर से आवागमन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे बनने से दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, चंडीगढ़ से शिमला तीन घंटे में सफर हो रहा है। अब तक चंडीगढ़ से शिमला का सफर 10 घंटे में पूरा होता था। उन्होंने कहा एक्सप्रेस वे एंव सड़कों के जरिये बीमार यूपी में विकास हो रहा है। इन एक्सप्रेस के बनने से किसानों की आय बढ़ी और आवागमन सुगम हुआ है। शायद इसी लिए लोकार्पण समारोह में किसानों ने शिरकत की है।

उ0प्र0 के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा : राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन के अनुरूप उत्तर प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सीएम योगी नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष्य रखा, जो निकट भविष्य में पूरा होकर रहेगा। आज प्रदेश में सात एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हैं।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को आईआईएम रोड

स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आयोजित 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे पीएम मोदी का करिश्मा ही कहा जाएगा कि 2014 के पहले भारत की अर्थव्यस्था आकार के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर थी, जो आज पांचवें स्थान आ गई है।

रक्षामंत्री ने कहा कि खरीदारी के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। दुनिया की जानीमानी वित्तीय फर्म मार्गन स्टेनले ने भारत को लेकर यह विश्वास व्यक्त किया है कि चार वर्षों में यानी 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अनिर्णय का शिकार थी। जनता में सरकार को लेकर विश्वास था। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, भ्रष्टाचार चरम पर था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी सरकार की ओर से शुरू की गई परियोजनाएं और योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही थी ना ही कोई नई परियोजना शुरू हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते नौ वर्ष में भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आज कोई दुश्मन भारत की ओर से टेढ़ी निगाह से नहीं देख सकता है।

महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नौ वर्ष पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने से विकास नहीं हो पाता था। इससे रोजगार के नए अवसर भी विकसित नहीं हो पाते थे। उन्होंने कहा कि लखनऊ

उन्होंने कहा कि लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए यहां पर वैसा ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। यहां पर लोकार्पित हुआ हाइवे एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे बड़ी संख्या में वाहन आ जा सकेंगे और लोगों के समय की भी बचत होगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर, केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री वीके सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद, समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण और अन्य नेता मौजूद थे।

2014 से पहले केंद्र सरकार अनिर्णय की शिकार थी : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले के डिफेंस कॉरिडोर में ब्रम्होस मिसाइल बनने जा रही है। योगी ने कहा कि विकास ही देश और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नई दिशा दे सकता है। 2014 से पहले देश में किसान शोषण का शिकार थे। उन्हें उनकी उपज का दाम नहीं मिल पाता था। आज पारदर्शी व्यवस्था के कारण किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है। मंडी की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हुआ है। इससे किसानों की आय कई गुना बढ़ी है। किसानों को उनका मुआवजा समय पर मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान पथ के निर्माण से लखनवासियों के आवागमन मार्ग सुगम हो जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर, केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री वीके सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद, समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरूण मौजूद थे।

सर्वांगपूर्ण राष्ट्र है

भारत सर्वांगपूर्ण राष्ट्र है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन लोकतंत्र है। यहाँ वैचारिक विविधता है। सभी विचारधाराओं का सहअस्तित्व है। यहाँ वैदिक काल से ही सभा और समितियां रहीं हैं। 'हम भारत के लोग' प्रकृति और संस्कृति से उदार हैं। विश्व कल्याण भारतवासियों का ध्येय रहा है। सम्प्रति भारत राष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। देश की अनतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है। लेकिन भारत की विश्व प्रतिष्ठा कथित उदारवादियों की आँख की किरकिरी है। वे सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करते रहते हैं। वे भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार चलाते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। आरोप लगते हैं कि अल्पसंख्यकों को सामान्य नागरिक अधिकार भी उपलब्ध नहीं हैं। जबकि सच इसका उल्टा है। यहाँ अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। उन्हें संविधान (अनु० 29–30) में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण शीर्षक से विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन्हें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का भी अधिकार है। ऐसे अधिकार बहुसंख्यकों को नहीं हैं। लोक नियोजन के सभी अवसर अल्पसंख्यकों को उपलब्ध हैं। वे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत से लेकर विधायक, सांसद और राष्ट्रपति तक चुने जाते हैं। न्यायपालिका के क्षेत्र में भी उनकी प्रतिष्ठा रही है और है। अर्थशास्त्र के विद्वान और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने 'देश की सम्पदा पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार' बताया था। यहां अल्पसंख्यकों को सभी नागरिक अधिकारों और अवसरों की समानता उपलब्ध है। बावजूद इसके कथित उदारवादी अल्पसंख्यक उत्पीड़न के बहाने भारत की प्रतिष्ठा पर हमलावर हैं। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की भी नकारात्मक टिप्पणी आई है। ऐसे वातावरण के बीच हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विश्व मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने भारत के ज्ञान और संविधान की प्रशंसा की है। उन्होंने भारत को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुन्दर उदाहरण बताया है।

अल इस्सा ने अपील की है कि शांति के सम्बंध में दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। उन्होंने भारत को अल्पसंख्यक उत्पीड़न का क्षेत्र बताने वाले कथित उदारपंथियों को आइना दिखाया है। भारत में पंथ मजहब आधारित भेदभाव कभी नहीं रहे। भारत के मूल अभिजन आर्य–हिन्दू हैं। यहाँ दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अनेक जनसमूह आते रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता के अध्येता अनेक विद्वानों ने हिन्दुओं द्वारा सबको गले लगाने व मिला लेने की क्षमता को अद्भुत बताया है। यहाँ बाहर से आए ईरानी, यूनानी, पार्थियन, बैक्ट्रियन, हूण, तुर्क, यहूदी और पारसी भी घुल मिल गए। मुसलमान सातवीं शताब्दी में आए। उनका आना काफी लम्बे समय तक जारी रहा। उन पर भी हिन्दू जीवन रचना का प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार

हृदयनारायण दीक्षित

विन्सेंट स्मिथ ने लिखा है कि, ''विदेशी (मुसलमान तुर्क) अपने पूर्वजों शकों आदि की तरह हिन्दू धर्म की आत्मसात करने की अद्भुत शक्ति के वश में हुए और उनमें तेजी से हिन्दूपन आ गया।'' वे भारतीय संस्कृति के प्रभाव में भारत के अभिजन बन गए। लेकिन पं० जवाहर लाल नेहरू ने स्मिथ द्वारा प्रयुक्त हिन्दू धर्म और हिन्दूपन शब्द प्रयोग पर आपत्ति की थी, ''इन शब्दों के इस्तेमाल से एक खास मजहब का ख्याल होता है।'' पं० नेहरू की दृष्टि में हिन्दू मजहब है। लेकिन उनका यह निष्कर्ष राजनैतिक है और सत्य से परे है। वस्तुतः हिन्दुत्व भारत के लोगों की जीवनशैली है। लेकिन नेहरू भारत के बाहर से आए लोगों के परस्पर मिल जाने की बात से इंकार नहीं करते।

मैक्समूलर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान थे। इंग्लैण्ड की सरकार ने 1882 में सिविल सेवक अंग्रेज युवकों को प्रशिक्षण के दौरान भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया था। उद्देश्य था कि नए सिविल अधिकारी भारत की आत्मा को उचित ढंग से समझ सकेंगे। मैक्समूलर के व्याख्यान 'इंडिया वाट कैन टीच अस' नाम से संग्रहीत हुए थे। उन्होंने संस्कृति दर्शन आदि उत्कृष्ट मूल्यों के लिए भारत को विश्व श्रेष्ठ बताया था। कथित उदारवादी मैक्समूलर के निष्कर्ष नहीं मानते। वे भारत में सभी आस्थाओं का सहअस्तित्व भी नहीं मानते। अमेरिका में श्वेत अश्वेत भेद रहे हैं। अश्वेतों का उत्पीड़न भी रहा है। इस पर टिप्पणी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर लम्बे अरसे से हिन्दू उत्पीड़न का क्षेत्र रहा है। कश्मीर घाटी को हिन्दू विहीन करने और कश्मीरी पंडितों–हिन्दुओं का नरसंहार भुलाया नहीं जा सकता। इस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। लेकिन कथित उदारवादी कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की गिरफ्तारी व उन पर कानूनी कार्रवाई को लेकर व्यथित रहते हैं।

भारत की प्रतिष्ठा कथित उदारपंथियों व अलगाववादियों को हजम नहीं होती। अलगाववाद इनका मुख्य एजेण्डा है। लेकिन भारत को तोड़ कर कोई भी राजनीति संभव नहीं हो सकती। भारतीय जन गण मन को असहिष्णु और हिंसक बताकर भी कोई राजनीति नहीं की जा सकती। भारत में विविधता के बावजूद एकता है। इस एकता को तोड़ने का प्रयास समाज के प्रति अपराध है। राष्ट्र सर्वोपरिता का आचरण भारतवासियों की संवैधानिक निष्ठा है। यहाँ सभी पंथिक आस्थाओं के प्रति सम्मान का स्वाभाविक वातावरण है। सबको अपने विचार के अनुसार पंथ मजहब के प्रति आस्तिकता और तत्सम्बंधी उपासना के संवैधानिक अधिकार हैं।

राष्ट्र के जन्म, गठन व राष्ट्र निर्माण का आधार मजहब नहीं होता। पाकिस्तान का जन्म और गठन मजहब के आधार पर हुआ था। लेकिन पाकिस्तान अपने जन्म के 24 वर्ष बाद टूट गया। मजहब ही राष्ट्र गठन का आधार होता तो पाकिस्तान मजबूत राष्ट्र होता। अलगाववादी विचार को लेकर जिन्ना भारत तोड़ने में कामयाब रहे। यह इतिहास का त्रासद अध्याय है और विघटनकारी राजनीति का प्रतिफल है। आखिरकार अपने ही समाज की निंदा और आलोचना का मूल लक्ष्य क्या है। विभाजनकारी राजनीति और राष्ट्रतोड़क बयानबाजी का उद्देश्य क्या है?

मुस्लिम वर्ल्ड लीग के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मानव केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने के तरीके व विभिन्न सांस्कृतिक अनुयायियों के मध्य समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने पर विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने उग्रवाद और नफरत के सभी पहलुओं का सामना करने के लिए सहमति जताई है। मानवीय मूल्यों को लेकर भारत का काम ऐतिहासिक रहा है। विश्व लोकमंगल प्राचीन काल से ही भारत का ध्येय रहा है। भारत ने कभी किसी दुसरे देश पर हमला नहीं किया। न कभी उपासना स्थल तोड़े गए और न ही आस्था विश्वास आधरित उत्पीड़न की घटनाएं हुईं। यहाँ सभी आस्थाओं, पंथों और मजहबों का सहअस्तित्व रहा है। अल इस्सा ने ठीक ही कहा है कि शांति के लिए सारी दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक सम्पदा विराट है। प्राचीन दर्शन और विज्ञान में भी भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा रही है। सभी पंथिक आस्थाओं का सहअस्तित्व भारतीय इतिहास का तथ्य है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या शांति और विभिन्न विचारधाराओं के सहअस्तित्व के सम्बंध में लोग भारत से प्रेरित होंगे और सीखेंगे? बेशक सीखेंगे। लेकिन इसके पहले भारत के छद्म सेकुलर और कथित उदारपंथी भारतीय संस्कृति के सत्य स्वीकार करें। भारत की प्रतिष्ठा का रथ चक्र तेज रफ्तार है। इसे रोका नहीं जा सकता।

17 से 21 जुलाई 1857

अंग्रेजों द्वारा कानपुर में भीषण नरसंहार

रमेश शर्मा

जलियाँवाला बाग में हुये सामूहिक नरसंहार को सब जानते हैं। पर अंग्रेजों ने इससे पहले और इससे भीषण नरसंहार भी किये हैं। इनमें एक भीषण नरसंहार जुलाई 1857 को कानपुर में हुआ। इसमें लगभग बीस हजार से अधिक निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया था। छै हजार का आंकड़ा तो अकेले कानपुर नगर का है।

इस नरसंहार के नायक जनरल नील और जनरल हैवलॉक नामक दो सैन्य अधिकारी थे। 1857 की क्रांति में कानपुर और बिठूर में केवल पांच दिनों तक चला यह भीषण नरसंहार अकेला नहीं है। इस क्रान्ति के दमन केलिये लगभग हर स्थान पर भीषण नरसंहार हुये। इनमें अधिकांश के वर्णन तो जिला गजेटियरों में है। लेकिन कानपुर का यह नरसंहार कितना भीषण होगा। इस बात का अनुमान केवल इस एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने इस क्रांति के दमन केलिये लगभग हर स्थान पर एक एक जनरल ही तैनात किये थे। जनरल ह्यूरोज की कमान में जो सेना थी उसने मध्य प्रदेश के महू से अपना अभियान आरंभ किया और इंदौर, सीहोर, गढ़ी, राहतगढ़, सागर, आदि स्थानों के बाद झाँसी कालपी और ग्वालियर में अभियान चलाया। जबकि अकेले कानपुर और बिठूर के लिए दो जनरल भेजे गये। वे भी ऐसे जो अपनी क्रूरता के लिये कुख्यात रहे। इसका कारण यह था कि 1857 में क्रांति का उद्घोष भले सिपाही मंगल पाण्डेय ने बंगाल इन्फ्रेन्ट्री से किया हो पर इसका मुख्य केंद्र कानपुर और मेरठ थे। इन स्थानों पर मई में क्रान्ति का आरंभ हुआ था। कानपुर में क्रान्ति के नायक नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे थे। इनके नेतृत्व में सेना ने विद्रोह कर दिया था और नाना साहब पेशवा ने कानपुर में सत्ता संभाल ली थी। यहाँ कुछ अंग्रेज परिवार रहते थे। नाना साहब ने इन अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित भेजने का प्रबंध किया था और इन्हें गंगा पार कराने केलिये सत्ती चौरा भेजा गया था। कुछ परिवार नावों में रवाना भी हो गये थे। किन्तु सत्ती चौरा में कुछ सैनिकों को गुस्सा आया और उन्होंने इन परिवारों पर हमला बोल दिया। इसमें कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष मारे गये। यह घटना 26 जून 1857 की है और इतिहास के पन्नों पर "सत्ती चौरा कांड" के नाम से जानी जाती है। इसमें मरने वाले अंग्रेजो की संख्या अलग–अलग बताई गई है। इस घटना से

अंग्रेज बौखलाए। उन्होंने क्रूरतम अंग्रेज अधिकारियों की कमान में सेना कानपुर भेजी। जनरल हैवलॉक और जनरल नील के कमान में ये सेनाएँ 16 जुलाई 1857 को कानपुर पहुँचीं। इन सैन्य दलों ने पूरे नगर को घेर लिया। ब्रिटिश अधिकारियों को पहले उम्मीद थी कि ब्रिटिश परिवार सुरक्षित होंगे किन्तु जैसे ही उन्हे अंग्रेज परिवारों के मरने की जानकारी मिली। तो उनका गुस्सा सॉंतवे आसमान पर पहुँच गया। और भारतीय नागरिकों का कत्लेआम शुरू कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है उस सशस्त्र सैनिक समूह की कार्यवाही का जिसके कार्यों की कोई अपील कोई दलील का प्रावधान ही न हो। वह पूरी तरह निरंकुश हो और प्रतिशोध पर उतारू हो। इन सैनिकों द्वारा कानपुर और बिठूर में किये गये कुछ अत्याचारों का तो ऐसा वर्णन है जिसका उल्लेख करने में भी आत्मा कांपती है। लूटपाट, तोड़फोड़ और घरों को जलाना तो बहुत मामूली था । यह सेना नागरिकों के साथ जितने अत्याचार कर सकती थी वे सब किये गये। जनरल नील ने आदेश दिया कि पकड़े गए सभी सिपाही विद्रोही माने जायें। उन्हे पकड़कर पहले बीबीघर परिसर ले जाया गया। सत्तीचौरा का बीबीघर वह स्थान था जहाँ कुछ अंग्रेज परिवारों की हत्या की गई थी। गुस्साए सैनिकों ने बंदी बनाये गये विद्रोही सैनिकों से उस फर्श को चाटने के लिए विवश किया गया, जहाँ अंग्रेज परिवारों का रक्त गिरा था। इसके बाद उन्हे गोली मारकर पेड़ों पर लटका दिया गया। जबकि कुछ को तोपों से बांध कर उड़ा दिया गया। उधर जनरल हैवलॉक ने कानपुर छावनी में उन 134 सैनिकों को भी गोली मार देने के आदेश दिये जो क्रान्ति से दूर होकर पुनः अंग्रेजों की सेवा करना चाहते थे। हैवलॉक और नील का कहना था कि इन्होंने ब्रिटिश परिवारों को बचाने का कार्य क्यों न किया। इसके बाद विद्रोह को संरक्षण देने और समर्थन देने वाले कस्बों की ओर सेना चली। इन कस्बों घेर कर आग लगा दी गई। गाँव के गाँव जलाये गये। जिस गाँव में आग लगाई जाती, उसे सेना पहले घेर लेती थी ताकि कोई जिन्दा बाहर निकल कर भाग न सके। इन गाँवों में मरने वालों की संख्या हर गाँव की अलग–अलग है किसी में एकसौबीस स्त्री पुरुष तो एक गाँव में दो हजार तक पहुँची। यह नरसंहार 17 जुलाई से आरंभ हुआ था। जो 21 जुलाई तक निरन्तर चला। इतिहास की विभिन्न पुस्तकों में उल्लेख है कि जीटी रोड के किनारे जितने भी गांव पड़े, उन सभी को हैवलॉक ने जला दिया था। राहगीरों को मार–मार कर पेड़ों पर लटकाया। कानपुर के वर्तमान के मेघदूत चौराहे पर फांसी का मंच बनाया गया था यहां मात्र तीन दिन में छह हजार स्त्री बच्चों की निर्ममता से हत्या की गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं नृत्यांगना अजीजनबाई की टोली ने यहीं अंग्रेजों से लोहा लिया था। अजीजनबाई को भी हैवलॉक ने ही मारा था।

कानपुर में यह सब करके जनरल हैवलॉक बिठूर पहुँचा। उसकी कमान में मेजर स्टीवेन्सन की एक सैन्य टुकड़ी भी थी। जिसमें मद्रास फ्यूसिलियर्स और पंजाब बलूच सैनिकों की संख्या अधिक थी। यहाँ इस सेना का प्रतिरोध करने वाला कोई न मिला। उसने पेशवा नाना साहब के महल पर कब्जा कर लिया और जो व्यक्ति सामने पड़ा उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ब्रिटिश सैनिकों ने पहले पेशवा के महल का सामान अपने अधिकार में लिया। जिसमें बंदूकें, हाथी और ऊंट और अन्य कीमती सामान था। और फिर महल में आग लगा दी। इसके बाद जैसा कत्लेआम कानपुर में किया था वैसा ही कत्लेआम बिठूर में किया।

हैवलॉक की क्रूरता की कार्रवाई की तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने प्रशंसा की और हैवलॉक के नाम को अमर करने केलिये भारत के अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम "हैवलॉक द्वीप" रखा। यह नाम स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षों तक यथावत रहा। इस नाम को पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलकर स्वराज द्वीप किया। हैवलॉक द्वारा कानपुर में किये गये अत्याचार के वर्णन इतिहास की पुस्तकों में भरे पड़े हैं। अंग्रेजों के कानपुर आपरेशन में हैवलॉक के साथ रहे कमांडर शेरर ने अपनी पुस्तक "हैवलॉक्स मार्च ऑन कानपुर" में भी इस नरसंहार और अत्याचार का वर्णन किया है। अंग्रेजों के ऐसे नरसंहार और अत्याचारों से इतिहास की पुस्तकों में तो हैं ही। हर जिले के गजेटियरों में भी हैं। पर आज की अधिकांश पीढ़ी इससे अनभिज्ञ है। यहाँ तक कि जिस हैवलॉक के अत्याचार से कानपुर का इतिहास भरा है उसी हैवलॉक के नाम पर बने द्वीप पर पिकनिक मनाकर गौरवान्वित हुआ करते थे। हाँ उस द्वीप का नाम बदलने से कुछ लोग चौंके और इतिहास के पन्ने पलटे। तब यह सच्चाई सामने आ सकी।

नीति व नेतृत्व पर एनडीए की बढ़त

विपक्षी गठबंधन ने अपने नामकरण के लिए भारी भरकम शब्दों का चयन किया। लेकिन उनकी राजनीति में इनका फिट होना मुश्किल है। विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया. यह जोड़ तोड़ कर बनाया गया नाम है। – इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमारा सभ्यतागत संघर्ष भारत और इंडिया के आसपास केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। हमें खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए।

वैसे इस नामकरण के चलते विपक्षी पार्टियों की जबाब देही बढ़ गई है। अब उन्हें यह बताना होगा कि डेवेलपमेंट के मुद्दे पर उनकी कितनी विश्वसनीयता है। यूपीए को दस वर्ष सरकार चलाने का अवसर मिला। पश्चिम बंगाल में डेढ़ दशक से तृणमूल की सरकार है। दिल्ली में आप सरकार को भी अवसर मिला। बताया गया कि गठबंधन बैठक मे शामिल हुए दलों की ग्यारह प्रदेशों में सरकारें हैं। लेकिन बिडम्बना देखिए कि बंगलुरु बैठक में किसी ने भी अपनी सरकारों के विकास कार्यो पर एक शब्द भी नहीं कहा। वह मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे। प्रजातंत्र, संविधान, सामाजिक सौहार्द की दुहाई देते रहे। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अभी बंगाल में हुए पंचायती चुनाव मे प्रजातंत्र और संविधान का कितना सम्मान हुआ। यह विधानसभा चुनाव के समय भी खूब हिंसा हुई थी। विपक्ष के अनेक नेता घोटालों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप कारवाई चल रही ही। इस वह संस्थाओं और प्रजातंत्र पर हमला बता रहे हैं। नेशनल हेराल्ड घोटाला, चारा घोटाला,नौकरी के बदले जमीन आदि प्रकरण अपने में बहुत कुछ

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

कहने वाले हैं। गठबंधन में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी शामिल है। कश्मीर में संवैधानिक सुधारों के दौरान इनके बयानों को देश भुला नहीं है। यह स्पस्ट होना चाहिए कि अन्य विपक्षी पार्टियां जम्मू–कश्मीर पर इनके विचारों का कितना समर्थन करेंगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अस्तित्व संकट में है। उसके प्रवक्ता कहते हैं कि अब बीजेपी को इंडिया के खिलाफ लड़ना होगा। मतलब मात्र नामकरण से ही इनका पूरे देश में प्रभाव कायम हो गया है। सीपीआई नेता डी राजा ने जो कहा वह बंगाल पर ज्यादा लागू होता है। उन्होंने सुरक्षा, प्रजातंत्र जैसे विषय उठाए। आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाया, निशाने पर बंगाल सरकार थी। महबूबा मुफ्ती आरोप लगाती हैं कि देश आंतरिक रूप उथल–पुथल के दौर से गुजर रहा है। जहां हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है। हमारे देश में सब कुछ दांव पर है। साफ है यह उनकी अपनी राजनीतिक पीड़ा अभिव्यक्त हो रही थी।

उमर अब्दुल्ला भी बेचैन हैं। जम्मू–कश्मीर के संवैधानिक सुधारों ने इनकी पुस्तैनी सियासत पर ग्रहण लगा दिया है। ममता बनर्जी से बंगाल संभल नहीं रहा है। वहां अराजकता का माहौल है। पंद्रह साल बाद भी वह विकास पर बात नहीं करतीं। लेकिन दावा करती हैं कि इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, देश जीतेगा, भाजपा हारेगी। राहुल गांधी विगत नौ वर्षो से एक ही अंदाज हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा कि यह लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच नहीं है। देश की आवाज को कुचला जा रहा है, यह लड़ाई देश के लिए है इसलिए इंडियन नेशनल डेवेलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (INDIA) नाम चुना गया। यह NDA और INDIA की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच लड़ाई है। उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच की लड़ाई है। भारत की संस्थाओं पर हमला हो रहा है। हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। ये लड़ाई भारत बनाम बीजेपी है। ये भारत बनाम पीएम मोदी की लड़ाई है। दिल्ली की बाढ़ आपदा से बेखबर अरविंद केजरीवाल भी बेंगलुरु पहुँचे थे। वह भी देश को बचाने के लिए बेकरार थे। एक तरफ देश को नफरत से बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेकर हम सब इकट्ठा हुए हैं।

दूसरी तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक में सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। नौ वर्षों में विकास के अभूत पूर्व कार्य हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। कहा कि 'इन लोगों को भ्रष्टाचार से इन लोग को बहुत प्रेम है। ये लोग परिवारवाद के समर्थक है। ये लोग परिवार प्रथम के लिए काम करते है। परिवारवादी पार्टी ने देश का विकास नहीं किया। बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा हुई लकिन इन पार्टियों ने कुछ नहीं बोला। शराब घोटाले पर भी ये पार्टियां कुछ नहीं बोलती है। भाजपा ने विपक्ष में भी सकारात्मक राजनीति की। कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। सरकारों का विरोध करने के लिए कभी विदेशी मदद नहीं मांगी. सत्ता की मजबूरी, परिवारवाद, गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। पहले सत्ता के गलियारे में जो बिचौलिए घूमते थे, हमने उनको बाहर कर दिया है। जन–धन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति से लगभग तीस लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में पहुंचे। लगभग तीन लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाया है। नौ वर्ष पहले देश की अर्थव्यवस्था टॉप दस से बाहर थी, आज देश पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है. नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा कि एक ही लक्ष्य है – विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि–कोटि लोगों का विकास. विपक्षी गठबंधन का नामकरण निरर्थक ही लग रहा है।

भारत और मिस्र की 'रणनीतिक साझेदारी'

अमेरिका की अत्यंत सफल राजकीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल–सिसी के निमंत्रण पर 24 जून को मिस्र पहुंचे। प्रधानमंत्री की यह पहली मिस्र यात्रा थी। हवाई अड्डे पर मिस्र के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा वहीं पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री सिसी ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान कृषि, पुरातत्व एवं पुरावशेष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात

अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल–सिसी ने 25 जून, 2023 को अल–इत्तिहादिया पैलेस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी की। दोनों नेताओं ने जनवरी, 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति श्री सिसी की राजकीय यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया और इससे द्विपक्षीय संबंधों को मिली गति का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर भी सहमति प्रकट की कि मिस्र की कैबिनेट में नव गठित 'इंडिया यूनिट' द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कारगर है।

दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के बीच विशेष रूप से व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों के बारे में चर्चा की।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति श्री सिसी ने खाद्य व ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के लिए मिलकर आवाज उठाने की आवश्यकता जैसे मुद्दों को रेखांकित करते हुए जी–20 में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सितंबर, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जी–20 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति श्री सिसी का स्वागत करने के प्रति उत्सुकता प्रकट की। दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि, पुरातत्व एवं पुरावशेष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर मिस्र के प्रधानमंत्री श्री मुस्तफा मैडबौली और उनकी कैबिनेट के कई अन्य वरिष्ठ मंत्री भी उपस्थित थे। भारत की ओर से विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मिस्र के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मिस्र के मंत्रिमंडल की 'भारत इकाई' के साथ बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचने के तुरंत बाद 24 जून को मिस्र के मंत्रिमंडल की 'भारत इकाई' के साथ एक बैठक की। इस

'भारत इकाई' की स्थापना इस वर्ष की शुरुआत में मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल–सिसी की गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजकीय यात्रा के बाद की गई थी। इस 'भारत इकाई' की अध्यक्षता मिस्र के प्रधानमंत्री श्री मुस्तफा मैडबौली करते हैं तथा इसमें कई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री मैडबौली और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों ने 'भारत इकाई' की विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की और सहयोग के नए क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने भारतीय समकक्षों की ओर से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में भारत–मिस्र द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति उत्सुकता जताई।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'भारत इकाई' की स्थापना की सराहना की और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इस 'संपूर्ण सरकार वाले दृष्टिकोण' का स्वागत किया। उन्होंने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में मिस्र के साथ मिलकर काम करने की भारत की तत्परता को साझा किया।

बैठक में व्यापार एवं निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, दवाओं और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री मैडबौली के अलावा इस बैठक में मिस्र के सात कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री काहिरा में अल–हकीम मस्जिद गए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मिस्र की राजकीय यात्रा के दौरान 25 जून को काहिरा में अल–हकीम मस्जिद गए। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्री डॉ. मुस्तफा वज़ीरी ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बोहरा समुदाय के नेताओं से भी मुलाकात की, जो इस फातिमीद युग की शिया मस्जिद के रख–रखाव में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उन्होंने भारत और मिस्र के लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंधों पर प्रकाश डाला।

श्री मोदी ने 24 जून को मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉ. शॉकी इब्राहिम अल्लम से भी मुलाकात की। ग्रैंड मुफ्ती ने हाल की अपनी भारत यात्रा को गर्मजोशी से याद किया और भारत एवं मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों तथा दोनों देशों के लोगों के बीच के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला। ग्रैंड मुफ्ती ने समावेशिता और बहुलतावाद को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना भी की।

चर्चा के केन्द्र में समाज में सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव और उग्रवाद एवं कट्टरपंथ से निपटने से जुड़े मुद्दे भी रहे। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार–अल–इफ्ता में आईटी से संबंधित एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करेगा।

प्रधानमंत्री ने हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का किया दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेटरी का दौरा किया। श्री मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपनी जान न्योछावर करने वाले 4300 से अधिक बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मिस्र में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून को काहिरा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत में श्री मोदी ने भारत–मिस्र संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए इस समुदाय की सराहना की। इस कार्यक्रम में छात्रों, पेशेवरों और व्यावसायियों सहित प्रवासी भारतीय समुदाय ने भारी संख्या में भाग लिया।

सरकार की उपलब्धियां

किसानों के लिए 3,70.128.7 करोड़ रूपये की नवीन योजनाओं को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 28 जून को 3,70,128.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी। योजनाओं का समूह टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। ये पहल किसानों की आय बढ़ायेंगी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को मजबूती देंगी, मिट्टी की उत्पादकता को पुनर्जीवित करेंगी और साथ ही खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगी।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को करों और नीम कोटिंग शुल्कों को छोड़कर 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम की बोरी की समान कीमत पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी। पैकेज में तीन वर्षों के लिए (2022–23 से 2024–25) यूरिया सब्सिडी को लेकर 3,68,676.7 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यह पैकेज हाल ही में अनुमोदित 2023–24 के खरीफ मौसम के लिए 38,000 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त है।

किसानों को यूरिया की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उनकी इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में यूरिया की एमआरपी 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी है (नीम कोटिंग शुल्क और लागू करों को छोड़कर), जबकि बैग की वास्तविक कीमत लगभग 2200 रुपये है। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित है। यूरिया सब्सिडी योजना के जारी रहने से जारी रहने से यूरिया का स्वदेशी उत्पादन भी अधिकतम होगा।

लगातार बदलती भू–राजनीतिक स्थिति और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर उर्वरक की कीमतें कई गुना बढ़ रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर अपने किसानों को उर्वरक की अधिक कीमतों से बचाया है। हमारे किसानों की सुरक्षा के अपने प्रयास में भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 2014–15 में 73,067 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022–23 में 2,54,799 करोड़ रुपये कर दिया है।

पिछले नौ वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59 प्रतिशत बढ़ी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 27 जून को कहा कि पिछले नौ वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59 प्रतिशत बढ़ी है। इस विस्तार के साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।

श्री गडकरी ने कहा कि 2013–14 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो 2022–23 में बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गयी, जो इस अवधि में 59 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। पिछले नौ वर्षों में फोर–लेन राष्ट्रीय–राजमार्ग में वृद्धि लगभग दोगुनी हो गई है। 2013–14 में फोर–लेन राष्ट्रीय–राजमार्ग की यह लंबाई 18,371 किलोमीटर थी, जो पिछले नौ वर्षों में बढ़कर 44,654 किलोमीटर हो गयी है। श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग को शुरु करने से टोल संग्रह में महत्वपूर्ण उछाल आया है। उन्होंने बताया कि टोल से राजस्व संग्रहण 2013–14 के 4,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022–23 में 41,342 करोड़ रुपए हो गया है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक टोल राजस्व संग्रहण को 1,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में सड़क राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है और इस क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से सड़क किनारों पर 670 सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। हरित पहल के मुददे पर श्री गडकरी ने कहा कि एनएचएआई ने पिछले नौ वर्षों में 68,000 से अधिक पेड़ों का प्रत्यारोपण किया, जबकि 3.86 करोड़ नए पेड़ लगाए। जल पुनर्जीवन पहल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनएचएआई ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 1500 से अधिक अमृत सरोवर विकसित किए हैं।

मोदी स्टोरी

मोदी का स्मार्ट चुनाव अभियान

—तेज बहादुर चौहान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपनी चुनावी रणनीतियों और लोगों से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके नवोन्वेषी सुझावों और लीक से हटकर विचारों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करना सिखाया है और उन्हें स्मार्ट बनाया है जिससे पिछले कई दशकों से भाजपा को पूरे देश में आगे बढ़ने में मदद मिली है।

2014 के बाद से विपक्षी दल श्री मोदी की चुनावी रणनीतियों के बारे में अनभिज्ञ रहे और यही एक कारण है कि देश ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है।

हालांकि, श्री मोदी के स्मार्ट और नवोन्वेषी चुनाव अभियान भाजपा में उनके शुरुआती दिनों से ही पार्टी को चुनाव जीतने में मदद करते आये हैं।

यह बात वर्ष 1997-98 की है जब श्री नरेन्द्र मोदी मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे और वह पार्टी की एक बैठक के लिए उज्जैन आये हुए थे।

मध्य प्रदेश के भाजपा नेता श्री तेज बहादुर चौहान उज्जैन में श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए बताते है कि श्री मोदी ने उनसे उनकी जिम्मेदारियों और पार्टी द्वारा सौंपे गये कार्यों के बारे में चर्चा की। इस पर श्री चौहान ने उत्तर दिया कि वह पार्टी के झंडे और पर्चे बांटते हैं, हर घर में जाते हैं, शहर भर में लोगों से मिलते हैं और मतदाताओं को भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं।

इसके बाद श्री मोदी ने उनसे उनके मूल स्थान को लेकर प्रश्न किया, साथ ही उनसे यह भी पूछा कि वह शहर भर में कितने झंडे बांटते हैं। श्री चौहान ने उत्तर दिया कि वे लगभग 15 हजार घरों वाले नागदा के निवासी हैं और शहर में 2500-3000 झंडे वितरित करते हैं।

उनका जवाब सुनकर श्री मोदी ने उनसे पूछा कि क्या आपके शहर में ऑटो रिक्शा चलते हैं। श्री मोदी के सवाल पर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए श्री चौहान ने हां में जवाब दिया। तब श्री मोदी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप 3000 पार्टी झंडे बांटने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको वांछित परिणाम न मिले, जबकि यदि आप शहर में विभिन्न ऑटो रिक्शा पर 50 पार्टी के झंडे लगा सकते हैं, तो वे पूरे शहर में घूमेंगे और घरों पर लगाए गए 3000 पार्टी के झंडों की तुलना में लोगों के बीच पार्टी के झंडे को अधिक पहुंच प्रदान करेंगे।

श्री मोदी के सुझाव को पाकर श्री चौहान आश्चर्यचकित रह गये। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह एक सामान्य विचार प्रक्रिया थी, लेकिन इसका उन्हें कभी आभास नहीं हुआ। उनका कहना है कि श्री मोदी के सुझाव से उन्हें स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद मिली और पार्टी के लिए बेहतर परिणाम मिले। ■

केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपये किए आवंटित

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 30 जून को स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) के तहत 19 राज्य सरकारों को 6,194.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी। इस राशि में वर्ष 2022-23 के लिए 4 राज्यों (छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) को एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 1,209.60 करोड़ रुपये और 15 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा) को वर्ष 2023-24 के लिए 4,984.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस धनराशि का उपयोग राज्य मौजूदा मानसून सीज़न के दौरान राहत उपायों के लिए कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 09 राज्यों को एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3649.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एसडीआरएफ के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ■

वैचारिकी

अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा

मुंबई में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय परिषद् में 28 दिसंबर, 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण का अंतिम भाग

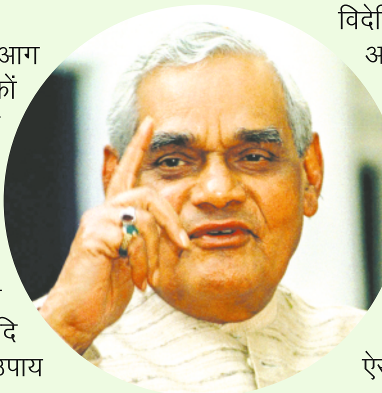

असम आंदोलन

असम जल रहा है। गत एक वर्ष से वहां आग लगी हुई है। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की घुसपैठ के कारण वहां के लोग अपने ही घर में पराए होते जा रहे हैं। घुसपैठ का सिलसिला दशकों से चल रहा है। मुझे याद है, 1957 में जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य बना तो मैंने इस घुसपैठ की ओर सरकार का ध्यान खींचा था। मैंने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि घुसपैठ को रोकने की कोई प्रभावी उपाय योजना नहीं की गई तो परिस्थिति विस्फोटक रूप धारण कर लेगी। किंतु सरकार ने समस्या की गंभीरता को नहीं पहचाना। असम में विदेशियों की समस्या का आकार मामूली नहीं है, जैसा बताने की कोशिश होती रही है। 1978 में जनता शासन के दौरान अकेले मंगलदोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 47,600 विदेशियों के नाम मतदाता सूची में पाए गए। 1957 से 1970 के बीच यहां मतदाता सूची में 12 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई, जबकि 1970 से 1979 के बीच यहां 28 लाख नए मतदाताओं के नाम दर्ज हुए।

असम में विदेशियों की समस्या

केंद्रीय सरकार के पिछले 12 महीनों के बर्ताव ने असम की समस्या को ज्यादा जटिल बना दिया है। सरकार ने कभी इसे असमी बनाम गैर–असमी का रंग देने की कोशिश की तो कभी असमी और बंगालियों में टकराव कराने की नीति अपनाई। कभी सवाल को हिंदू बनाम मुसलमान का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन असम में विदेशियों की समस्या को असली रूप में देखने से हमेशा इनकार करती रही।

असम सीमा प्रदेश है। यह भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से भारत का सिंहद्वार है। प्राकृतिक दृष्टि से मनोहारी असम तेल, खनिज, वनसंपदा, जलस्रोतों और संस्कृति की दृष्टि से बड़ा संपन्न है। किंतु आज भी असम निर्धन है, निरादृत है, शोषित है, शापित है। असमी लोग अपने आर्थिक पिछड़ेपन के लिए केंद्र को दोषी मानते हैं। उन्हें यह भी शिकायत है कि उनकी भाषा तथा अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति अवहेलना का रवैया अपनाया गया है।

केंद्रीय सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच बातों के जो अनेक दौर हुए हैं, उनके फलस्वरूप मतभेद घटे हैं और अब गतिरोध इस बात पर है कि 1961 से 1971 के बीच आए विदेशियों का क्या किया जाए। सरकार उन्हें असम से बाहर बसाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आंदोलन के नेता सारा बोझ असम पर डालने को उचित नहीं मानते।

दोनों पक्षों को इस मामले में अपने कड़े रुख में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। बीच का रास्ता यह हो सकता है कि 1961 से 1971 के बीच आए लोगों को पहचानने तथा मतदाता सूची में से उनके नाम काटने पर दोनों पक्ष सहमत हो जाएं। ऐसे लोगों को असम में ही रहने दिया जाए या अन्य प्रदेशों में बसाया जाए, इस सवाल का निर्णय नई मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचित नई सरकार पर छोड़ दिया जाए।

असम सरकार का गठन एक संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ था, अब उसे बनाए रखने का कोई संवैधानिक, नैतिक या व्यावहारिक औचित्य नहीं है। उसे तुरंत बरखास्त कर देना चाहिए।

जनांदोलन को दबाना अनुचित

असम के जनांदोलन को गोली या गिरफ्तारी से नहीं दबाया जा सकता। जिस आंदोलन के साथ लगभग हर असमिया पुरुष, नारी तथा बच्चे की भावनाएं जुड़ी हैं, उसको केवल कानून तथा व्यवस्था के मामले के रूप में निबटाना आत्मघात होगा। दमन का रास्ता अमन का रास्ता नहीं हो सकता।

विदेशी घुसपैठ को बढ़ावा

असम की वर्तमान स्थिति के लिए वे राजनीतिक नेता दोषी हैं, जिन्होंने स्वार्थसिद्धि के लिए न केवल विदेशी घुसपैठ को अनदेखा किया, अपितु उसे बढ़ावा देने का अपराध भी किया। असम की आत्मा में पहले से ही बहुत से घाव लगे हैं। शेष भारत अपनी उदासीनता और केंद्रीय नेतृत्व अपनी अदूरदर्शिता से असम के पूर्ण विनाश का पाप न करे।

आर्थिक स्थिति : 1977 और 1980

देश के आर्थिक संकट को गहरा करने के लिए वर्तमान सरकार की नीतियां या नीतियों का पूर्ण अभाव, जिम्मेदार है। चीन में वर्षों का नामकरण करने की परंपरा है। वे किसी वर्ष को चंद्रमा का वर्ष और किसी को सिंह का वर्ष पुकारते हैं। यदि हम उनका अनुकरण करें तो श्रीमती गांधी के प्रथम वर्ष को 'घोंघे का वर्ष' कहना पड़ेगा। इसकी तुलना में जनता शासन के दो वर्ष दौड़ते हुए घोड़े के वर्ष थे।

विकास की धीमी गति

गत वर्ष आर्थिक मोरचे पर पूरी जड़ता छाई रही। ऐसा लगा, मानो काल थम गया है। सबसे बुरा पहलू यह है कि सरकार को यह पता भी नहीं चला कि सबकुछ ठप है। वित्तमंत्री श्री वेंकटरमण बार–बार अपने आंकड़े बदलते रहे। उन्होंने जून में, जब अपना विनाशकारी बजट पेश किया था, यह कहा था कि औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10 फीसदी तक की वृद्धि होगी। अब उन्हें स्वीकार करना पड़ा है कि वृद्धि 4 फीसदी से अधिक नहीं होगी। हमेशा की तरह इस बार भी वह गलत साबित होंगे। औद्योगिक विकास गत वर्ष से 2 प्रतिशत ही अधिक होगा।

बढ़ती मुद्रास्फीति

मूल्यवृद्धि को रोकने के आश्वासन पर चुनी गई सरकार के एक साल में दो ही चीजों में वृद्धि हुई हैकृ पहला, मूल्य और दूसरा, शेयर बाजार शेष सबकुछ नीचे ही नीचे जा रहा है। जनता के शासनकाल में राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होगी। जनता शासन में औद्योगिक उत्पादन 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा था, इस वर्ष यह केवल 2 प्रतिशत बढ़ेगा। जनता शासन में मूल्य स्थिर थे, उनमें नाममात्र की भी वृद्धि नहीं हुई थी, इस वर्ष उनमें 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और वे लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने जनता पार्टी को एक अच्छी अर्थस्थिति सौंपी थी और जनता ने उसको तहस–नहस कर दिया। वह भूल जाती है कि 1976–77 में जनता शासन के एक वर्ष पूर्व सूखा पड़ा था। सूखा गत वर्ष भी पड़ा था। फिर भी जनता सरकार ने अच्छे परिणाम दिखाए तथा अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ; अब स्थिति उलट गई है।

घटता विदेशी मुद्रा भंडार

अच्छी आर्थिक स्थिति अच्छे विदेशी मुद्रा भंडार में दिखाई देती है। जनता शासन में विदेशी मुद्रा में 2350 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी और जब हमने सरकार छोड़ी तो देश के पास 5200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी। राष्ट्र की संपत्ति को उड़ाया जा रहा है। केंद्रीय सरकार तथा योजना आयोग इस बात के लिए अपनी पीठ आप थपथपाते हुए नहीं थकते कि छठीं पंचवर्षीय योजना को बड़ी फुर्ती से अंतिम रूप दे दिया गया है। तथ्य यह है कि जनता शासन द्वारा तैयार पुरानी योजना को ही कांट–छांट तथा लीप–पोतकर नई योजना के रूप में पेश कर दिया गया है। इसके लिए सरकार को क्षमा किया जा सकता है। किंतु अब जो कुछ होनेवाला है और जिसके लिए शासन को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, वह है योजना को पूरी तरह रद करने की तैयारी। जिस तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं, उससे योजना एक कागजी खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं रही है।

हम इस बात पर संतोष करके न बैठें कि दुनिया के प्रथम 10 औद्योगिक देशों में भारत की गिनती होती है। हमारा स्थान पांचवां क्यों न हो? दुनिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। छोटा देश दक्षिण कोरिया जैसे भी हमें मीलों पीछे छोड़ चुका है। देश की अर्थव्यवस्था साइकिल पर चढ़े व्यक्ति की तरह होती है; पैडल चलाना बंद करते ही सवार गिर जाता है। सरकार पैडल चलाना कभी का बंद कर चुकी है। अब तो वह गिरनेवाली है।

देश तकदीर के तिराहे पर

किंतु सवाल केवल सरकार के गिरने या पूरी तरह विफल हो जाने का नहीं है। लोकतंत्र में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। सवाल तो यह है कि भारत राष्ट्र अपनी मूल्य–व्यवस्था के आधार पर वर्तमान काल की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में समर्थ होगा या नहीं। मित्रो, स्थिति गंभीर है। देश एक बार फिर तकदीर के तिराहे पर खड़ा है। एक ओर अधिनायकवाद का खतरा है, तो दूसरी ओर अराजकता का संकट है। दोनों का सामना करने के लिए हमें लोगों को संगठित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी टकराव की राजनीति को पसंद नहीं करती। किंतु हम टकराव से कतराएंगे भी नहीं।

लोकतंत्र की रक्षा

भारतीय लोकतंत्र के प्राण 65 करोड़ लोगों की समानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं। जो लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोकचेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के इस संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं तथा उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथास्थिति को एकजुट होकर बदलने से ही पूरा होगा। लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का आह्वान भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में तथा राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिन लद गए। जोड़–तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य अब नहीं रहा। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होनेवालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फूले हमारे पथ–प्रदर्शक होंगे।

कमल खिलेगा, देश के पश्चिमी घाट को मंडित करनेवाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं यह भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि 'अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।' वंदेमातरम्

'कारगिल विजय दिवस पर विशेष:

भारत के शूरवीरों ने चटाई थी पाकिस्तान को धूल'

1999 में 60 दिनों तक चले कारगिल युद्ध में हमारे 527 से अधिक वीर योद्धा बलिदान हुए थे। भारत माता के इन सपूतों ने अपने प्राण देकर भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परम्परा का निर्वाह कर पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी और भारत का 'ऑपरेशन–विजय' सफल हुआ था।

1965 और 1971 में भारत के हाथों मिली कड़ी पराजय की टीस पाकिस्तानी सेना के मन में हमेशा से रही है। पूरी दुनिया यह बात जानती है कि वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का ही है, आज तक पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। सेना का जब मन चाहा तब तख्ता पलट दिया। 1971 में जब पाकिस्तान भारत से युद्ध हार गया तो लंबे समय तक शांति रही। इस बीच भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं आमने सामने नहीं आईं। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आया बीचकृबीच में वह भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा। 1984 में 'ऑपरेशन अबाबील' भी पाकिस्तान ने शुरू किया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। इसके तहत पाकिस्तान की सियाचिन में घुसपैठ करने की कोशिश नाकाम कर दी गई दी और भारतीय सेना ने वहां कब्जा ले लिया। इस ऑपरेशन के असफल होने की टीस सेना प्रमुख बनने के बाद भी मुशर्रफ के मन में रही, जो 1999 के कारगिल युद्ध के रूप में बाहर आई। मुशर्रफ ने अपनी किताब 'इन द लाइन ऑफ फायर' में इस बात का उल्लेख भी किया है।

1990 में कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद की शुरुआत हुई थी जो आज तक जारी है। 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। इस समय परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सेना के प्रमुख थे। परमाणु परीक्षण के बाद पैदा हुई तनाव की स्थिति पर बातचीत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्वक हल के लिए प्रयास करने को राजी हुए।

3 मई को पाकिस्तान की सेना की तरफ से कारगिल में घुसपैठ की जानकारी स्थानीय चारवाहों से भारतीय सेना को मिली। 5 मई को भारतीय सेना के गश्ती दल को धोखे से बंधक बना लिया गया। उन्हें यातनाएं देकर मारा गया। 9 मई को पाकिस्तानी सेना की तरफ से भंयकर गोलाबारी की गई। 10 मई को द्रास, काक्सर और मुश्कोह क्षेत्र में घुसपैठ होने का पता चला। इस पर सेना ने कुछ और सैन्य दलों को कारगिल की तरफ भेजा। इसके बाद लगातार युद्ध चला और धीरेकृधीरे भारत ने अपनी सभी चोटियों पर कब्जा ले लिया। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया। 26 जुलाई को औपचारिक रूप से सेना से कारगिल युद्ध समाप्त होने की घोषणा की और ऑपरेशन विजय पूरा हुआ।

दो महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। भारत के रणबांकुरों ने अपना जीवन बलिदान कर मातृभूमि की रक्षा की थी। लखनऊ कारगिल पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारत की सीमाओं की तरफ अगर कोई कुदृष्टि डालेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा।

श्रद्धांजलि

कार्य मंत्र के अनुसार कार्य आगे बढ़ाएंगे - डॉ. भागवत'

अपने संपर्क में आए हुए हर व्यक्ति को विचारों और आंतरिक स्नेह से प्रेरित कर किसी न किसी काम में, सामाजिक कार्य में सक्रिय करने का बहुत बड़ा कार्य मदनदास जी ने किया. उनकी दी हुई सीख पर आचरण करते हुए काम बढ़ाना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन जी भागवत ने मदनदास जी देवी को श्रद्धांजलि समर्पित की। उन्होंने कहा कि हम मदनदास जी के दिए हुए कार्यमंत्र के अनुसार कार्य आगे बढाएंगे।

ज्येष्ठ प्रचारक तथा संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह मदनदास जी देवी का 24 जुलाई को प्रातः बेंगलुरु में निधन हो गया था। उनका पार्थिव आज सुबह पुणे लाया गया। मोतीबाग स्थित कार्यालय में अंतिम दर्शन हेतु रखा गया था। उसके बाद वैकुंठ शमशान भूमि में मदनदास जी के भतीजे राधेश्याम देवी ने अंतिम संस्कार किए। मैं जब उनके संपर्क में आया, तब भी मैंने यह अनुभव किया। बाल आयु की शाखा के मित्रों से लेकर विभिन्न संगठनों के प्रमुखों तक के कार्यकर्ताओं से उनका निकट संपर्क था। वे सबकी चिंता करते थे. हर एक की उन्हें पूरी जानकारी होती थी।

उन्होंने कहा कि मदनदास जी का स्नेहस्पर्श हुआ यह मैं अपनी कृतार्थता मानता हूं। मदनदास जी संगठन और विचारों के पक्के थे। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय वे यह ध्यान रखते थे कि व्यक्ति का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। यशवंतराव केलकर से आदर्श लेकर उन्होंने काम बढ़ाया। मनुष्य को मोह बिगाड़ता है। इस सबके पार जाकर ध्येय के प्रति समर्पित कार्यकर्ता उन्होंने तैयार किए। उनसे काफी कुछ सीखने जैसा था. उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। लेकिन मेरे जाने के बाद यह काम बिना रूके आगे बढ़ता जाए, यह सीख उन्होंने दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद मराठे ने कहा कि मदनदासजी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वैचारिक आधार बिछाने और कार्यकर्ताओं में संगठन के दर्शन को विकसित करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया।

जे. पी. नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने कहा कि मदनदासजी ने देश के हजारों कार्यकर्ताओं को कर्म की दृष्टि दी, उन्हें जीवन की दिशा दी, उन्हें संस्कार दिये और जीवन को उद्देश्य दिया। सभी युवाओं को हमेशा यह महसूस होता था कि वे उनके वरिष्ठ सहकर्मी हैं। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हेतु मंगलवार को साधारण कार्यकर्ताओं से लेकर उच्चपदस्थ मंत्रियों तक सभी स्तरों के सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। अवसर पर मदनदास जी के भाई खुशालदास देवी, भगिनी और परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे। मदनदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में सरसंघचालक मोहन जी भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी होसबाले, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेशजी सोनी जी, अनिरुद्ध देशपांडे जी, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत कार्यवाह डॉ. प्रवीण दबडधाव, पूर्व प्रांत कार्यवाह विनायकराव थोरात, अभाविप के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पाचपोर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे, वरिष्ठ कार्यकर्ता गीताताई गुंडे, गिरीश प्रभुणे आदि शामिल थे।

लखनऊ माधव सभागार निराला नगर में श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए भैया जी जोशी ने कहा कि तत्व निष्ठ, ध्येयनिष्ठ, मदन जी को सच्ची श्रद्धांजलि उनकी ध्येय साधना में अपने को समर्पित करने से होगी, सभा में रा0स्व0 संघ के श्री स्वत्तरंजन जी, अनिल जी, धर्मपाल सिंह भाजपा संगठन महामंत्री, मनोज कान्त, रामजी सिंह, ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा, सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

73 %

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2022-23
जुलाई द्वितीय 2023 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

विकास पथ पर उत्तर प्रदेश

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।